

## भारतीय दंड संहिता में नस्लीय भेदभाव वरिधी प्रावधान

### संदर्भ

गृह मंत्रालय ने भारतीय दंड संहिता में दो सख्त नस्लीय भेदभाव वरिधी प्रावधानों को सम्मलिति करने के लयि कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव राज्यों के समक्ष रखा था। केंद्र के इस प्रस्ताव पर मात्र चार राज्यों तथा तीन केंद्र शासति प्रदेश को छोड़कर शेष राज्यों एवं केंद्र शासति प्रदेशों ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है।

### प्रमुख बदि

- गृह मंत्रालय के इस प्रस्तावति संशोधन पर उत्तर प्रदेश, मणपुर, मेघालय और मज़ोरम ने अपनी सहमति दी है।
- इससे पहले अंडमान-नकिोबार, दादर और नगर हवेली और लक्षदीप भी केंद्र के इस प्रस्ताव से सहमत हो चुके हैं।
- 26 जुलाई को गृह राज्य मंत्री करिन रजिजि ने राज्यसभा को बताया था कि उनका मंत्रालय नस्लीय अपराधों से नपिटने के लयि आईपीसी की दो धाराओं (धारा 153ए और धारा 509ए) में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है।

### राज्य का वषिय

- चूंकि प्रस्तावति संशोधन संवधान की समवर्ती सूची के तहत आता है, इसलयि इसमें राज्य सरकारों की राय प्राप्त करना आवश्यक है। इस मामले में राज्यों को इस साल फरवरी में पत्र भेजे गए थे।

### बेजबुरुआ समति की सफारशों

- प्रस्तावति संशोधन पूर्वोत्तर के लोगों पर नस्लीय हमलों के मद्देनज़र फरवरी 2014 में केंद्र द्वारा गठति बेजबुरुआ समति की सफारशों पर आधारति है।
- बेजबुरुआ समति ने जुलाई 2014 में अपनी रपिोर्ट प्रस्तुत की थी।
- गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तावति मसौदा आईपीसी की धारा 153 सी के प्रावधान के तहत दोषी को पाँच साल तक कारावास एवं जुर्माना की सज़ा दी जाएगी।
- हालाँकि इसके दुरुपयोग की भी संभावनाएँ जताई जा रही हैं, वशिष रूप से आईपीसी की धारा 509ए को लेकर जसिके तहत कसि शब्द या इशारे को, जोकि एक अपराध है, साबति करना मुश्कलि है।